Volunteers of Handicapped School

3397. SHRI SURESH PACHOURI: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government through UGC are providing assistance to the volunteers of the Handicapped schools;

(b) if so, how many volunteers were provided training through NCERT;

(c) whether there is a great shortage of volunteers for handicapped schools in Madhya Pradesh; and

(d) if so, the reasons therefor and the action taken by government in this regard?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPART OF EDUCATION AND DEPARTMENT OF CULTURE) (KUMARI SELJA): (a) AND (b) No, Sir. However, financial assistance has been provided through the University Grants Commission (UGC) under the Centrally Sponsored Scheme of Integrated Education for the Disabled Children (IEDC) for organising training courses in special education for teachers of handicapped children in some Universities and Institutions.

(c) and (d) There is no report of shortage of volunteers for handicapped schools in Madhya Pradesh.

भारतीय ओलम्पिक संघ की ओर से प्रस्ताव

3398. **श्री राम गोपाल यादव : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार को खिलाड़ियों को दी जा रही सुविधाओं से स्तर में सुधार लाने के संबंध में भारतीय ओलम्पिक संघ की ओर से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल) संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री मुकुल वासनिक) : (क) और (ख) भारतीय ओलम्पिक संघ ने खिलाड़ियों को प्रदान की जा रही सुविधाओं के स्तर में सुधार करन के लिए प्रस्ताव भेजा है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल उपस्कर, विदेशी प्रशिक्षक, वैज्ञानिक समथन, यात्रा भत्ता का प्रावधान शामिल है जिसमें भोजन, आवास, हवाई अड्डा कर, वीजा फीस, विदेशों में प्रतियोगिताओं के लिए सहभागिता फीस किट, खुराक भत्ते में संशोधन आदि की व्यवस्था भी शामिल है । इन सुझावों की जांच की गई है और उनमें से अधिकतर संशोधित मार्गदर्शी सिद्धान्तों में शामिल किए गए हैं जो कि विचाराधीन है। संबंधित संघों के परामर्श से अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उपस्कर प्राप्त करने और विदेशी प्रशिक्षकों को लगाने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है ।

Businesscourses at school level

3399. SHRIMATI CHANDRIKA ABHINANDAN JAIN: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-item appearing in 'The Economic Times' of 4th July, 1993 under the caption 'HP plans to start bdsiness courses at school level";

(b) if so, what is the reaction of Government thereto; and

(c) whether Government are considering similar proposal for schools located in Delhi?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF EDUCATION AND DEPARTMENT OF CULTURE) (KUMARI SELJA): (a) Yes Sir.

(b) The Central Government supports the initiatives of state Government in their efforts to introduce job-oriented courses including business course at the school level. Assistance is given under the Centrally Sponsored Scheme of Vocationalisation of Secondary Education started with effect from February, 1988.

(c) State Governments/UTs are free to introduce vocational courses/trades selected by them in accordance with the demand.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन उपक्रमों/संस्थाओं में भ्रष्टाचार के मामले

3400. श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन उपक्रमों/संस्थाओं में भ्रष्टाचार के मामलों के संबंध में सूचना मिली है ;

(ख) यदि हां, तो कितने अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई है और कितने अधिकारियों को नौकरी से निकाला गया है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि जिन व्यक्तियों के विरूद्ध भ्रष्टाचार और कदाचारों के आरोप लगाए गए थे, उनका सजा के तौर पर केवल स्थानांतरण किया गया है ; और

(घ) सरकार भ्रष्टाचार और कदाचार में लिप्त अधिकारियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) (ग) से (घ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

हिमाचल प्रदेश में नवोदय विद्यालयों का खोला जाना

3401. श्री महेश्वर सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री 8 मई, 1993 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 1460 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और लाहौल-स्पीति जिलों में नवोदय विद्यालयों को खोलने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए है ;

(ख) यदि हां, तो कब और उन पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ; और

(ग) क्या कुल्लू जिले में जरड़ नामक स्थान पर केन्द्रीय विद्यालय खोलने हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) जी हां । नवोदय विद्यालय समिति ने सूचित किया है कि इन दो जिलों में नवोदय विद्यालय स्थापित करने के लिए प्रस्ताव दिसम्बर, 1987 में प्राप्त हुए हैं । तथापि, ये प्रस्ताव नवोदय विद्यालयों की स्थापना के मानदण्डों को पूरा नहीं करते हैं । हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वे नए प्रस्ताव भेजें जो जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने के लिए मानदण्डों को पूरा करते हों ।

(ग) जी, नहीं ।

Schools covered under operation black-board in Punjab

3402. SHRI IQBAL SINGH: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) what was the total number of primary schools in Punjab which were provided essential facilities under the scheme of Operation Black Board started in 1987-88;